

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1786

दिनांक 05 दिसंबर, 2024

तेल की वैश्विक कीमतों में अस्थिरता

†1786. डॉ. अमर सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मासिक रूप से आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा और आयात मूल्यों का देश-वार व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान वैश्विक तेल आपूर्ति प्रवृत्तियों और घरेलू तेल की कीमतों पर उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों में वैश्विक अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है/अपनाए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा आयातित तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): चालू वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित कच्चे तेल की मात्रा के व्यौरे निम्नवत हैं:

वित्त वर्ष	मात्रा हजार मीट्रिक टन में (टीएमटी)
2019-20	2,26,955
2020-21	1,96,461
2021-22	2,12,382
2022-23	2,32,700
2023-24 (पी)	2,34,262
2024-25 (अप्रैल-अक्टूबर) (पी)	1,40,170

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ,

(पी): अनंतिम

(ख) और (ग): सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय तेल उपक्रमों (पीएसयूज) ने किसी एक क्षेत्र से कच्चे तेल की निर्भरता संबंधी जोखिम को कम करने हेतु तथा क्रूड आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्रूड बास्केट का विविधिकरण किया है और विभिन्न भौगोलिक स्थलों में स्थित देशों अर्थात मध्य पूर्व, अफ्रीका, उत्तर अमरीका, दक्षिण अमरीका आदि से क्रूड की अधिप्राप्ति कर रहे हैं।

(घ): सरकार ने कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने और उर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देना, मांग विस्थापन पर जोर देना, जैवईंधनों तथा अन्य वैकल्पिक ईंधनों/नवीनीकरणीय ईंधनों को बढ़ावा देना, ईवी चार्जिंग सुविधाओं और रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार शामिल हैं। सरकार ने सिंगल विंडो व्यवस्था सहित अनुमोदन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करते हुए निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी और राष्ट्रीय तेल कंपनियों को कार्यात्मक स्वतंत्रता भी प्रदान की है।

इसके अलावा, सरकार ने देश में जैवईंधनों की उपलब्धता बढ़ाने एवं एथेनॉल मिश्रण, जैव डीजल मिश्रण एवं किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) योजनाओं के माध्यम से एथेनॉल, जैव-डीजल और जैव-सीएनजी जैसे वैकल्पिक स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जैवईंधन नीति, 2018 की शुरूआत की है।
